क्या VRS से BSNL स्वस्थ होगा ?

IIM-अहमदाबाद द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद VRS गरमागरम चर्चा का विषय बन चुका है। BSNL के रिवाइवल/ रिस्ट्रक्चरिंग पर IIM-अहमदाबाद ने अपनी रिपोर्ट के पार्ट D में 50 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों के लिए VRS की अनुशंसा की है और साथ ही रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटा कर 58 करने की भी।

BSNL कर्मियों में से युवा वर्ग के साथी, विशेष रूप से डायरेक्टली रिक्रूटेड कर्मचारी, VRS और रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटा कर 58 किए जाने का जोर शोर से (vociferously) स्वागत कर रहे हैं। वें ऐसा महसूस करते हैं कि इन उपायों (measures) से BSNL वर्तमान संकट से उबर जाएगा और इससे उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। 50 या अधिक आयु वर्ग के भी कई कर्मचारी VRS का स्वागत कर सकते हैं। यह इसलिए, कि BSNL की वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण दौर में है और वेतन का भुगतान भी अब एक बड़ी समस्या बन चुका है।

BSNL मैनेजमेंट की 35000 कर्मचारियों को VRS देने की मंशा है। इसके क्रियान्वयन के लिए भारी भरकम धनराशि की जरूरत है। सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहाँ से ? BSNL अपने बूते इतनी बड़ी राशि खर्च नही कर सकता है। और यह भी तय है कि इतनी बड़ी राशि सरकार भी BSNL को VRS लागू करने हेतु नही देगी।

किन्तु, ज्यादा अहम प्रश्न तो ये है कि कर्मचारियों की युवा पीढ़ी जिस तरह से सोच रही है, VRS और रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटा कर 58 किए जाने से क्या BSNL स्वस्थ हो जाएगा ? कदापि नही। उन्हें यह समझना होगा कि BSNL की बीमारी की वजह कर्मचारियों की विशाल संख्या नही, वरन सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियां हैं। सरकार का वास्तविक उद्देश्य BSNL को स्वस्थ कर लाभ अर्जन करनेवाली कंपनी में परिवर्तित करना नही है। सरकार का इरादा BSNL के वर्कफोर्स की संख्या कम करना है, जिससे कि BSNL को किसी निजी कॉर्पोरेट को बेचना आसान हो सके। वास्तव में, सरकार की सदैव यह रणनीति रही है कि, निजी कंपनीज को सुदृढ बनाएं और सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदाता को कमजोर करें। यह निम्न तथ्यों से समझ जा सकता है।

- मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस 1995 में प्रदान किए गए थे। DoT, जो उस समय सरकारी सेवा प्रदाता था, को मोबाइल लाइसेंस नही दिया गया। BSNL को मोबाइल सेवाएं शुरू करने की अनुमति 2002 में मिली। इसके पीछे सरकार की मंशा निजी कंपनियों को एक अवसर उपलब्ध कराने की थी, जिससे कि वो मार्किट पर कब्जा कर सके।

- बहरहाल, 2004 तक BSNL एयरटेल को पछाड़ते हुए मोबाइल सेगमेंट में नंबर वन बनने की स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद 6-7 वर्षों तक BSNL को आवश्यक उपकरण प्राप्ति की अनुमति नही दी गई। मोबाइल उपकरण हेतु BSNL द्वारा निकाले गए टेंडर एक एक कर सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए। इस प्रकार सरकार ने स्वयं ही BSNL के मोबाइल नेटवर्क के विस्तार में अवरोध उत्पन्न किए।

- यह भी एक सच्चाई है कि 2004-2005 में इसी BSNL ने, कर्मचारियों की संख्या एक लाख अधिक होने के बावजूद, रु 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था। जाहिर है, BSNL की गिरावट का वास्तविक कारण कर्मचारियों की अधिकता नही है। ये सरकार की निजी समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियां हैं, जो BSNL को खत्म कर रही है।

- MTNL में दो बार VRS योजना लागू की गई। लेकिन, MTNL की स्थिति में सुधार नही हुआ, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब ही हुई। अतः स्पष्ट है कि BSNL की बीमारी का निदान VRS नही है।

- वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि सरकार किस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिलायंस जियो को सहयोग कर रही है। सभी नियम कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिससे कि रिलायंस जियो का सम्पूर्ण टेलीकॉम मार्किट पर कब्जा हो सके। श्री जे एस दीपक, तत्कालीन टेलीकॉम सेक्रेटरी, को DoT से अनौपचारिक तरीके से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था, कि उन्होंने रिलायंस जियो के लागत से भी कम मूल्य (predatory pricing) का विरोध किया था। हम यह भी देख ही रहे हैं कि किस तरह रिलायंस जियो भारतीय रेलवे और देश के सभी एयरपोर्ट का सेवा प्रदाता बन गया है। अतः, यह कांच की तरह साफ है कि सरकार रिलायंस जियो को ही बढ़ाना (promote) चाहती है, BSNL को नही।

- हाल ही में, सारा देश इस बात का गवाह है कि सरकार किस तीव्रता से जेट एयरवेज की मदद के लिए (bail out) आगे आयी है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बैंक्स को निर्देशित किया है कि वें जेट एयरवेज को रु 1500 करोड़ उपलब्ध करा कर सहायता करें। उधर दूसरी ओर, वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे BSNL के प्रति सरकार का रवैया उदासीन (indifferent) और बेरुखीपूर्ण (callous) है। सरकार इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है ?

हमें यह समझना चाहिए कि मूल रूप से सरकार की आर्थिक नीतियां, BSNL सहित सभी सरकारी उपक्रमों (PSUs) का निजीकरण करने की है। विगत 18 वर्षों में सरकार ने BSNL का निजीकरण करने की कई बार कोशिशें की हैं। किंतु सभी यूनियन्स और एसोसिएशन्स ने इनके खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष कर सरकार के प्रयासों को विफल किया है।

सब्सिडियरी टॉवर कंपनी लाने का सरकार का निर्णय, और कुछ नही, BSNL का निजीकरण करने की ही रणनीति थी। अब चर्चाएं हो रही हैं कि BSNL के ऑप्टिक फाइबर सब्सिडियरी कंपनी को सौंप दिए जाएं। यदि इसकी अनुमति मिल जाती है, तो हमारी फाइबर एसेट्स का 'रणनीतिक विक्रय' के माध्यम से निजीकरण हो जाएगा। अतः BSNL की सम्पूर्ण वर्क फोर्स को एकता के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे VRS और रिटायरमेंट की आयु सीमा कम करने के प्रयासों का विरोध करना चाहिए।

****